



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 394]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 4, 1982/भाद्र 13, 1904

No. 394]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 4, 1982/BHADRA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में उठा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1982

कां०आ० 649(अ)/18एफ०ए०/18ए/आई०डी० आर०ए०/82:-
केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० कां०आ० 128(अ)/18 एफ०ए०/18क/उ०वि०वि०अ०/73, तारीख 5 मार्च, 1973 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का सम्पूर्ण प्रबन्ध 5 मार्च, 1972 से पांच वर्ष की अवधि के लिये ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कां०आ० 146(अ)/18क/18क/उ०वि० वि०अ०/78, तारीख 2 मार्च, 1978, सं० कां०आ० 145(अ)/18क/18क/उ०वि०वि०अ०/80 तारीख 5 मार्च, 1980, सं० कां०आ० 144 (अ)/81, तारीख 4 मार्च, 1981, सं० कां०आ० 685 (अ)/18क/18क/उ०वि०वि०अ०/81, तारीख 4 सितम्बर, 1981 और सं० कां०आ० 121(अ)/18 एफ०ए०/18 ए/आई०डी०आर०ए०/82 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

675 GI/82

को उक्त औद्योगिक उपक्रम का 4 सितम्बर, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अतिरिक्त अवधि के लिये, प्रबन्ध करते रहने के लिये प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार, ने अपनी यह राय होने पर कि सर्वसाधारण के हित में यह समीचीन है कि प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखें, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबन्ध एक वर्ष की और अवधि के लिये जारी रखा जाये,

और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 2 सितम्बर, 1982 के, आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध एक वर्ष की और अवधि तक जारी रखने के लिये अनुज्ञात कर दिया था,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18क के साथ पठित धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत व्यक्ति को निदेश देती है कि वह 5 सितम्बर, 1982 से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखें।

[कां०सं० 2(1)/80 के०००शु०]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 4th September, 1982

ORDER

S.O. 649(E)/18FA/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 128(E)/18FA/18AA/IDRA/73, dated the 5th March, 1973, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973.

And whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 146(E)/18FA/18AA/IDRA/78, dated the 3rd March, 1978, No. S.O. 145(E)/18FA/18AA/IDRA/80, dated the 5th March, 1980, No. S.O. 144(E)/81, dated the 4th March, 1981, No. S.O. 685(E)/18FA/18AA/IDRA/81, dated the 4th September, 1981, and S.O. 123(E)/18FA/18AA/IDRA/82 dated the 4th March, 1982, the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for further periods upto and inclusive of 4th September, 1982.

And whereas the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of one year.

And whereas the said High Court, by its Order dated the 2nd September, 1982, permitted the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year.

And, now in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA, read with section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year commencing from the 5th September, 1982.

[F. No. 2(1)/80-Cus.]

C. K. MODI, Jt. Secy.